

इंजीनियरिंग में बेरोजगारी घटाने की कवायद...

अभी 25% रोजगार, बचे 75 के लिए सरकार बनाएगी एजेंसी

**जल्द बनेगी
केन्द्रीयकृत प्लेसमेंट
एजेंसी, तकनीकी
शिक्षा विभाग की
बैठक में निर्णय**

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क

rajasthanpatrika.com

जयपुर. प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों से निकल कर अपने दम रोजगार खोजने वाले या बेरोजगार रह जाने वाले करीब 70-75 प्रतिशत छात्रों के लिए सरकार जल्द ही रोजगार पाने का एक केन्द्रीय मंच प्रदान करेगी। यह सेंट्रलाइज्ड प्लेसमेंट एजेंसी होगी, जो सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के पास आउट छात्रों को प्रदेश में संचालित उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराएगी। इसके लिए यह एजेंसी पहले स्थानीय उद्योगों से उनकी जरूरत जानेगी और उसी हिसाब से छात्रों को प्लेसमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई तकनीकी शिक्षा विभाग की बैठक में यह निर्णय किया गया। यह एजेंसी तकनीकी विश्वविद्यालय के अधीन कार्य करेगी, जिसकी नोडल एजेंसी जयपुर स्थित सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सीईजी होगा। माहेश्वरी ने बताया कि सरकार की मंशा है कि कॉलेजों से निकले छात्र बड़ी कम्पनियों का इंतजार नहीं करें।



अभी यह है हाल

- प्रदेश में करीब 130 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं
- करीब 30 हजार छात्र हर साल पास आउट होते हैं
- इनमें से सिर्फ 25-30 प्रतिशत को ही प्लेसमेंट मुहैया हो पाता है
- कम प्लेसमेंट का कारण पुराना पाठ्यक्रम और इसमें उद्योगों की जरूरत के अनुसार बदलाव न होना है।
- फिलहाल बड़े कॉलेज अपने स्तर पर अलग-अलग प्लेसमेंट कराते हैं, अब इसके अलावा सरकार भी सहायता करेगी।

इंजीनियरिंग में स्पोकन इंगलिश और मानवीय मूल्य

तकनीकी शिक्षा विभाग इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में स्पोकन इंगलिश और मानवीय मूल्य जैसी विषयवस्तु भी शामिल करने की तैयारी में है। इसके लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद की बैठक 11 जुलाई को तय की गई है।

ऐसे पाठ्यक्रम बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालयों में शामिल है। सरकार ऐसे स्टार्टअप्स को भी प्रोत्साहित करने के लिए उन स्टार्टअप को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जो स्थानीय स्तर की आवश्यकता और मांग को भी पूरा कर सकें।

उद्योगों में स्थानीय को वरीयता

सूत्रों के अनुसार सरकार इस मामले में उद्योग विभाग को भी शामिल करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उद्योग विभाग के जरिए

विभिन्न स्थानीय उपक्रमों को अपने यहां नौकरियों में 15-20 प्रतिशत स्थानीय ग्रेजुएट्स को नियोजित करने के निर्देश दिए जा सकते हैं।